भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 260
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)

260. **श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का ब्यौरा दें साथ ही साथ फंड की शुरूआत के बाद से यूनिवर्सल सर्विस लेवी के संग्रह की स्थिति का ब्यौरा दें;
(ख) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि इस निधि का उपयोग अपर्याप्त रहा है, और यदि हां, तो इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न परियोजनाओं में इसके उपयोग सहित इसका ब्यौरा क्या है; और
(घ) यूएसओएफ के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूएसओएफ) की स्थापना दिनांक 01.04.2002 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत की गई थी। 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) कर दिया गया है। डीबीएन अल्पसेवित ग्रामीण, सुदूरवर्ती और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुंच और डिलीवरी को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए अधिदेशित है। डीबीएन

के क्रेडिट की शेष राशि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, डीबीएन के अंतर्गत सार्वभौमिक अभिगम लेवी के रूप में कुल 1,62,871.64 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं।

दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, डिजिटल भारत निधि की विभिन्न स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित 83,726 करोड़ रुपए की राशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। डीबीएन की विभिन्न स्कीमों के लिए संवितरित/उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in) पर उपलब्ध है।

डीबीएन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह भारतनेट, 4जी सैचुरेशन परियोजना, आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का प्रावधान, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, मेघालय में मोबाइल सेवाएं, अरुणाचल प्रदेश में और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं आदि सहित विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं को शामिल कर रहा है।

*****